NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 10 Sep, 2025

Edition: InternationalTable of Contents

Page 01 **Syllabus :GS 2 : Indian Polity & Constitution / Prelims**	सी.पी. राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति
Page 02 **Syllabus :GS 1 & 2 : Social Issues & Social Justice / Prelims**	खराब नारी रैंकिंग दिल्ली में महिला सुरक्षा अंतराल को उजागर करती है
Page 04 **Syllabus :GS 2 : International Relations/ Prelims**	नेपाल में हिंसा दिल दहला देने वाली, मोदी ने सामान्य स्थिति की अपील की
Page 06 **Syllabus :GS 3 : Environment & Ecology/ Prelims**	केंद्र सरकार ने निकोबार परियोजना से संबंधित वन अधिकारों की शिकायत पर 'तथ्यात्मक रिपोर्ट' मांगी
Page 11 **Syllabus :GS 1 : Social Issues / Prelims**	भारत के लिए सबक: केरल तेजी से शहरीकरण से कैसे निपट रहा है
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus :GS 3 : Science & Technology**	तकनीकी स्वतंत्रता की ओर लंबा मार्च

Page 01: GS 2 :Indian Polity & Constitution / Prelims

भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चुनाव न केवल संसदीय अंकगणित के संदर्भ में बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच व्यापक वैचारिक प्रतिस्पर्धा में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास का प्रतीक है।

C.P. Radhakrishnan elected Vice-President

The NDA nominee got 452 first preferential votes against Opposition candidate who got 300 votes

While 14 MPs abstained, 15 votes were found to be invalid; full electoral college comprises 788 electors

Voting pattern shows that the nationalistic ideology has emerged victorious, says Radhakrishnan

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan was elected the 17th Vice-President of India on Tuesday by a margin of 152 votes. The Opposition fell short of its own expected tally, even as 98.2% of the total electorate, comprising members of both Houses of Parliament, cast their ballot.

Mr. Radhakrishnan – the ruling National Democratic Alliance's nominee – got 452 first preferential votes against the joint Opposition candidate Justice B. Sudershan Reddy, who got 300 votes. Fifteen votes were found to be invalid and 14 MPs abstained.

Including the strength of both Houses, the full electoral college comprises 788 electors. With six vacancies in the Rajya Sabha and one in the Lok Sabha, this tally was reduced to 781 for the election.

Out of this, 767 electors cast their vote before the polling closed at 5 p.m. Rajya Sabha Secretary-General P.C. Mody, the Returning Officer for the election, announced the results.

Cross-voting

Though the Opposition declared the final count a "moral victory", it still fell short of its own estimated strength of 324, despite having managed to get nearly all of its members to vote. On the other hand, the NDA and others aligned with the government, which had an presumed strength of 439, seem to have managed an additional 13 votes, indicating cross-voting from the Opposition's ranks.

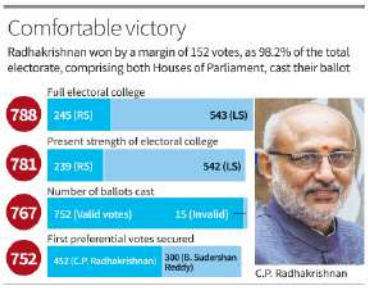

"Congratulations to Thiru CP Radhakrishnan Ji on winning the 2025 Vice Presidential election. His life has always been devoted to serving society and empowering the poor and marginalised. I am confident that he will be an outstanding VP, who will strengthen our Constitutional values and enhance Parliamentary discourse," Prime Minister Narendra Modi posted on X.

Other senior Ministers and BJP leaders also congratulated Mr. Radhakrishnan.

Congress president Mallikarjun Kharge extended his wishes to Mr. Radhakrishnan, while also thanking Justice Reddy for putting up a "spirited and principled fight" on behalf of the Opposition. Calling it an ideological battle, he said, "We hope the new Vice President-elect will uphold the highest ethos of Parliamentary traditions, ensuring equal space and dignity for the Opposition, and not succumb to pressures of the ruling dispensation."

In a concession statement, Justice Reddy said that he humbly accepted the outcome. "Our democracy is strengthened not by victory alone, but by the spirit of dialogue, dissent and participation. I remain committed, as a citizen, to upholding the ideals of equality, fraternity, and liberty that bind us together. May our Constitution continue to be the guiding light of our national life," he said.

In his first public remarks after the win, Mr. Radhakrishnan said, "The other side camp (opposition alliance) said that this (election) is an ideological fight, but from the voting pattern, we understand that the nationalistic ideology has emerged victorious." He said, "It is a victory for every Indian; we all have to work together. If we have to develop Viksit Bharat by 2047, which means we should not do politics in everything, now we will have to concentrate on development."

BJP leaders were quick to claim that at least 15 Opposition MPs had voted in favour of Mr. Radhakrishnan. BJP MP Sanjay Jaiswal claimed that "nearly 40 Opposition MPs" had listened to the voice of their conscience and voted in "some manner" in support of the NDA candidate, showing a wider acceptance for him. His assertion of support from 40 Opposition MPs appeared to include several invalid votes.

Countering this claim, Congress communications chief Jairam Ramesh insisted that the Opposition stood united. "Its performance has undeniably been most respectable. Its joint candidate Justice (retd) B. Sudershan Reddy secured 40% of the vote. In 2022, the Opposition had received 26% of the vote in the Vice Presidential Elections. The BJP's arithmetical victory is really both a moral and political defeat.," he said on X.

RELATED REPORTS
» PAGE 5

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **चुनाव परिणाम (2025):**
   - एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को**452 प्रथम वरीयता वोट मिले**।
   - विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी को **300 वोट मिले**।
   - **15 अवैध वोट** और **14 अनुपस्थित**दर्ज किए गए।
   - जीत का अंतर: **152 वोट।**
2. **इलेक्टोरल कॉलेज:**
   - इसमें **788 निर्वाचक** (संसद के दोनों सदन) शामिल थे।
   - 7 रिक्तियों के साथ, प्रभावी टैली: **781**।
   - मतदान: **767 सांसदों (98.2%) ने** अपना वोट डाला।
3. **क्रॉस-वोटिंग और राजनीतिक प्रभाव:**

- एनडीए ने अपनी अनुमानित ताकत से अधिक ~ 13 वोट हासिल किए, जो विपक्ष के क्रॉस-वोटिंग का संकेत देता है।
- विपक्ष के प्रदर्शन (40% वोट) को 26 के वीपी चुनाव में 2022% की तुलना में "नैतिक जीत" माना गया।

4. **वक्तव्य एवं प्रतिक्रियाएं:**
   - पीएम मोदी ने इस जीत को "संवैधानिक मूल्यों और विकसित भारत 2047 को मजबूत करने" **की दिशा में एक कदम के रूप में सराहना की**।
   - विपक्षी नेताओं ने संसदीय परंपराओं को बनाए रखने **और असहमति को जगह देने** के बारे में चिंताओं को उजागर किया।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71, भारतीय संविधान):**
  - राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद।
  - **राज्य सभा के पदेन सभापति** (अनुच्छेद 64)।
  - दोनों सदनों के सांसदों से मिलकर एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है (अनुच्छेद 66)।
  - कार्यकाल: **5 वर्ष**; फिर से चुना जा सकता है।
- **चुनाव विधि:**
  - गुप्त मतदान के माध्यम से **एकल हस्तांतरणीय वोट (एसटीवी) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के** माध्यम से आयोजित किया जाता है।
  - राष्ट्रपति चुनावों के विपरीत, कोई राज्य विधायिका की भागीदारी नहीं है।
- **हाल के उपाध्यक्ष:**
  - जगदीप धनखड़ (2022-2025), एम. वेंकैया नायडू (2017-2022)।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. प्रीलिम्स पॉइंटर्स:

- अनुच्छेद: **63-71 (भारत के उपराष्ट्रपति), अनुच्छेद 64 (राज्यसभा अध्यक्ष), अनुच्छेद 66 (चुनाव)।**
- चुनाव प्रणाली: **अप्रत्यक्ष, एसटीवी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान**।
- राष्ट्रपति के चुनाव से अंतर (राज्य विधानसभाएं वीपी चुनाव में मतदान नहीं करती हैं)।
- वर्तमान पदाधिकारी: **सीपी राधाकृष्णन (17वें उपाध्यक्ष, 2025)।**

2. मुख्य विश्लेषण (जीएस-II: राजनीति और शासन):

- **संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना:**
  - उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति **के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते** हैं, जो सरकार और विपक्ष के बीच शिष्टाचार और संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
  - वैचारिक मुकाबला उपराष्ट्रपति चुनावों को न केवल प्रक्रियात्मक बल्कि राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक भी दिखाता है।
- **क्रॉस-वोटिंग और राजनीतिक संकेत:**
  - क्रॉस-वोटिंग 2022 की तुलना में उच्च वोट शेयर के बावजूद विपक्षी एकता को कमजोर करने का सुझाव देती है।
  - पार्टी की आंतरिक गतिशीलता और अंतरात्मा के मतदान को दर्शाता है।
- **"विकसित भारत 2047" कथा में भूमिका:**

- एनडीए ने परिणाम को राष्ट्रवादी विचारधारा और विकास-प्रथम राजनीति **के समर्थन के रूप में तैयार किया**।
- उपराष्ट्रपति सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप विधायी चर्चा के सूत्रधार के रूप में

- **विपक्ष का नैतिक दृष्टिकोण:**
  - हालांकि चुनावी रूप से हार गया है, विपक्ष **अपने राजनीतिक समेकन में प्रगति के रूप में** 40% हिस्सेदारी का अनुमान लगाता है।
  - बहुमत की राजनीति के तहत **संसदीय परंपराओं, समान स्थान और असहमति को बनाए रखने** के बारे में चिंता व्यक्त करता है।
- **लोकतांत्रिक और संवैधानिक महत्व:**
  - भारत में **अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कामकाज को** मजबूत करता है।
  - पार्टी लाइन के भीतर भी स्वतंत्र **अंतरात्मा के मतदान** के महत्व पर जोर देता है।

निष्कर्ष

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चुनाव एक नियमित संवैधानिक घटना से कहीं अधिक है; यह भारतीय लोकतंत्र के भीतर **सत्तारूढ़ और विपक्षी ताकतों के बीच चल रही वैचारिक लड़ाई** का प्रतीक है । जबकि एनडीए इसे अपने विकासात्मक और राष्ट्रवादी एजेंडे की जीत के रूप में देखता है, विपक्ष **बहुलवाद, असंतोष और संसदीय संतुलन के महत्व पर जोर देता है**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे भाग नहीं लेते हैं।

2. दोनों चुनाव एक ही संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

3. उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव खुले मतपत्र द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (क)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: "2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए मजबूत संवैधानिक पद आवश्यक हैं। इस संदर्भ में, प्रभावी संसदीय प्रवचन सुनिश्चित करने में उपराष्ट्रपति की भूमिका के महत्व की जांच करें। **(250 शब्द)**

Page 02:GS 1 &2 : Social Issues &Social Justice/ Prelims

भारत के शहरी केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2012 के निर्भया मामले के बाद नीतिगत उपायों के बावजूद, दिल्ली का प्रदर्शन खराब है, जैसा कि **महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक** (**एनएआरआई**) 2025 द्वारा उजागर किया गया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी को निचले चार शहरों में रखा है। यह लैंगिक सुरक्षा के प्रति बुनियादी ढांचे, पुलिसिंग और सामाजिक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

Daily News Analysis

Poor NARI ranking exposes women safety gaps in Delhi

Ashna Butani
NEW DELHI

Thirteen years after the 2012 bus gang rape and murder shocked the nation, women in Delhi continue to face glaring safety gaps in everyday public life.

From poorly lit streets and unsafe transport to the lack of secure public spaces and limited emergency services, the concerns remain stark, according to the National Annual Report & Index on Women's Safety (NARI) 2025.

The survey, launched by the National Commission for Women (NCW) last month, covered 12,770 women across 31 cities.

Delhi ranked 28th on the women's safety index, placing it among the worst-performing cities, ahead only of Kolkata, Srinagar, and Ranchi.

Over 30% of women in Delhi said women-friendly infrastructure was either minimal or non-existent. FILE PHOTO

According to the report, 31% of women in Delhi said women-friendly infrastructure was either "minimal" or "non-existent".

'Serious concern'

Nationally, the figure stood at 23%. "This ranking is a serious cause for concern, particularly because Delhi, as the national capital, should ideally set the benchmark for women's safety across Bharat," the report said.

In Delhi, 41% of women said deserted spaces made them feel unsafe, while unlit areas, high crime rates, and public behaviour were also cited as reasons for fear.

The contrast between daytime and nighttime safety was sharp: while 8% felt unsafe during the day, the number jumped to 35% after dark.

The report noted that there is a "concerning disparity" between Delhi and the national average regarding experiences of harassment in public spaces.

The national capital recorded a higher incidence of harassment in public spaces compared with the national average. While 7% of women across the country reported experiencing harassment, in Delhi, the figure was 12%.

Repeated harassment

Alarmingly, 61% of Delhi women who reported harassment said they had faced it more than twice, pointing to systemic lapses in deterring repeat offenders. Neighbourhood areas were most frequently cited as sites of harassment (34%), indicating that proximity to home does not guarantee safety. This was followed by transport facilities (32%).

When asked for solutions, 51% of women demanded more policing, while 17% specifically called for timely and proper police action, underscoring frustration with law enforcement.

Cities that ranked higher than the national average included Kohima, Visakhapatnam, Aizawl, Bhubaneswar, Gangtok, Itanagar, and Mumbai. Faridabad ranked 27th, just above Delhi. The NARI report, ideated and funded by Pvalue Analytics, was released on August 28 and marks the first such national safety index.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **नारी 2025 सर्वेक्षण (राष्ट्रीय महिला और मूल्य विश्लेषण आयोग):**
   - नमूना आकार: **31 शहरों में 12,770 महिलाएं**।
   - दिल्ली **28वें स्थान** पर है, जो केवल कोलकाता, श्रीनगर और रांची से ऊपर है।
2. **दिल्ली पर सर्वेक्षण के निष्कर्ष:**
   - **31% महिलाएं**: महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचा "न्यूनतम या गैर-मौजूद" है (राष्ट्रीय औसत: 23%)।
   - **सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न:** 12% (बनाम राष्ट्रीय औसत 7%)।
   - **बार-बार उत्पीड़न:** 61% पीड़ितों ने दो बार से अधिक इसका सामना किया।
   - **असुरक्षित क्षेत्र:** पड़ोस के क्षेत्र (34%), परिवहन सुविधाएं (32%)।
   - **दिन-रात का अंतर:** दिन के दौरान 8% असुरक्षित, **अंधेरे के बाद 35%।**
   - **मांगे गए समाधान:** 51 प्रतिशत ने अधिक पुलिसिंग की मांग की; 17 प्रतिशत ने समय पर और उचित पुलिस कार्रवाई की मांग की।
3. **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर:** कोहिमा, विशाखापत्तनम, आइजोल, भुवनेश्वर, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **निर्भया मामला (2012):** न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की सिफारिशें, **आपराधिक कानून में संशोधन (2013),** महिलाओं की सुरक्षा के लिए **निर्भया कोष** का निर्माण किया गया।
- **प्रासंगिक कानून और पहल:**
   - **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013**—यौन उत्पीड़न की परिभाषा का विस्तार किया, कड़ी सजा।
   - **हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत** वन स्टॉप सेंटर
   - **प्रौद्योगिकी संचालित सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के तहत** सुरक्षित शहर परियोजना (एमडब्ल्यूसीडी + एमएचए)।

- **महिला हेल्पलाइन (181),दिल्ली पुलिस हिम्मत ऐप**, मेट्रो में गुलाबी बसें/विशेष कोच।
- **संवैधानिक समर्थन:**
  - अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (कोई भेदभाव नहीं), अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार)।
- **SDG-5 (लैंगिक समानता):** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने का आह्वान करता है।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. प्रीलिम्स पॉइंटर्स:

- नारी 2025 कोराष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया →, **जिसका विचार** पीवैल्यू एनालिटिक्स **द्वारा किया गया** है।
- दिल्ली की रैंकिंग: 31 **शहरों में से** 28 **वें।**
- निर्भया फंडद्वारा वित्त पोषित सुरक्षित शहर की पहल।

2. मुख्य विश्लेषण (जीएस-I, जीएस-II, जीएस-IV):

- **शहरी अवसंरचना अंतराल:**
  - खराब रोशनी वाली सड़कें, असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और निगरानी तकनीक की कमी जोखिम को बढ़ा देती है।
  - दिल्ली का बुनियादी ढांचा कोहिमा और गंगटोक जैसे छोटे शहरों से भी पीछे है।
- **पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन के मुद्दे:**
  - उच्च दोहराव उत्पीड़न (61%) **कमजोर निवारण और अपर्याप्त पुलिस अनुवर्ती कार्रवाई** को दर्शाता है।
  - जनता का अविश्वास महिलाओं में परिलक्षित होता है जो न केवल अधिक पुलिस बल्कि *बेहतर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं*।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम:**
  - पड़ोस में उत्पीड़न **पितृसत्तात्मक मानसिकता और सड़क उत्पीड़न के सामान्यीकरण का सुझाव देता है**।
  - सुरक्षा केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि **व्यवहार परिवर्तन और नागरिक जागरूकता के बारे में भी है**।
- **नीति और शासन विरोधाभास:**
  - सबसे अधिक ध्यान देने वाली राष्ट्रीय राजधानी **होने के बावजूद**, दिल्ली छोटे, संसाधन-सीमित शहरों से पीछे है।
  - यह नीतिगत इरादे और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन **के बीच बेमेल को इंगित करता है**।
- **एसडीजी-5 और राष्ट्रीय नीति के लिए निहितार्थ:**
  - महिलाओं की सुरक्षा सीधे गतिशीलता, **शिक्षा**, **कार्यबल की भागीदारी से जुड़ी हुई है**→ **जो** भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए महत्वपूर्ण है।
  - लगातार सुरक्षा अंतराल लैंगिक समानता और समावेशी शहरीकरण **की दिशा में भारत की प्रगति को कमजोर करते हैं**।

निष्कर्ष

नारी 2025 महिला सुरक्षा सूचकांक **में दिल्ली का खराब प्रदर्शन** कानूनी सुधारों, नीतिगत पहलों और जमीनी हकीकत **के बीच की खाई को रेखांकित करता है**। निर्भया के एक दशक से अधिक समय बाद, राजधानी शहर बुनियादी ढांचे, पुलिसिंग और सामाजिक दृष्टिकोण में प्रणालीगत विफलताओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। भारत के लिए सबक स्पष्ट है: सच्ची लैंगिक सुरक्षा प्राप्त करने **के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है** - **बेहतर शहरी नियोजन**, **उत्तरदायी पुलिसिंग**, **तकनीकी हस्तक्षेप और गहन**

सामाजिक परिवर्तन। इन अंतरालों को दूर किए बिना, **एसडीजी**-5 **और राष्ट्रीय शहरी नीति के तहत सुरक्षित**, **समावेशी शहरों** का दृष्टिकोण अधूरा रहेगा।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: **निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार से जुड़ी है?**

1. निर्भया फंड
2. वन स्टॉप सेंटर
3. सुरक्षित शहर परियोजना
4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर :a)

यूपीएससी मुख्य अभ्यास प्रश्न : सामाजिक मुद्दे

प्रश्न: चर्चा करें कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा चुनौतियां शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में कैसे योगदान दे सकता है? **(150 शब्द)**

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य अभ्यास प्रश्न : शासन और सामाजिक न्याय

प्रश्न: महिलाओं की सुरक्षा न केवल कानून-व्यवस्था की समस्या है, बल्कि शहरी नियोजन, सामाजिक दृष्टिकोण और शासन का भी सवाल है। एनएआरआई 2025 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न : नैतिकता

प्रश्न: सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा न केवल एक शासन चुनौती है, बल्कि सामाजिक नैतिकता की परीक्षा भी है। इस संदर्भ में, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में नागरिकों, समुदायों और संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page : 04: GS 2 : International Relations/ Prelims

भारत के निकटतम पड़ोसी और करीबी ऐतिहासिक साझेदार नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद व्यापक हिंसा देखी जा रही है। इस उथल-पुथल के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए नेपाली सेना की तैनाती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा को 'दिल दहला देने वाली' करार दिया और नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। भारत के लिए, यह विकास **विदेश नीति, पड़ोस संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के तहत महत्वपूर्ण है**।

Violence in Nepal heart-wrenching, Modi says in appeal for normalcy

The MEA says that India is 'closely monitoring' the unfolding situation in Nepal; officials maintain that India's cautious approach is governed by the understanding that given the political situation, New Delhi should adopt a neutral stance

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

The unfolding violence in Nepal is "heart-wrenching", Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday appealing directly to Nepal citizens and urging them to restore normalcy in their country, which has been rocked by protests over the past three days leading to the resignation by Prime Minister K.P. Sharma Oli.

"The violence that has happened in Nepal is heart-wrenching. My heart is extremely disturbed by the fact that many young people have lost their lives. Nepal's stability, peace and prosperity are of utmost importance. I humbly appeal to all my brothers and sisters in Nepal to maintain peace and order," said Mr. Modi as Nepal Army announced that it will take over the responsibility of law and order from 10 p.m. of Tuesday. Mr. Modi was on a tour of Himachal Pradesh for flood assessment during the day and chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security Affairs upon returning to Delhi where a "detailed discussion" was held on Nepal. Mr. Modi posted his message on social media platforms in Nepali.

On fire: People look at a burnt police vehicle during protests against the social media ban and corruption in Kathmandu on Tuesday. AP

Earlier, the Ministry of External Affairs said that India is "closely monitoring" the unfolding situation in Nepal as Prime Minister Oli resigned a day after Nepal police shot dead at least 19 young people who were protesting against his government during what is being described as "Gen-Z" uprising. Officials here maintained that India's cautious approach is governed by the understanding that given the heated political situation in Nepal, New Delhi should not be seen as supportive of any side in this uprising.

"We are closely monitoring the developments in Nepal since yesterday and are deeply saddened by the loss of many young lives. Our thoughts and prayers are with families of deceased. We also wish speedy recovery for those who were injured," said the MEA. Officials here said the ground situation might become a bit clear in a couple of days when many of the stakeholders in the protest would come out with their plans. "As a close friend and neighbour, we hope that all concerned exercise restraint and address any issues through peaceful means and dialogue," the MEA said.

The MEA \advised Indians to defer travel to Nepal in view of the situation. They are advised to follow safety advisories from Nepal authorities and the Embassy of India, Kathmandu, on the following helpline numbers: +977-980-860-2881 and +977-981-032-6134 (WhatsApp call also in both). Foreign Secretary Vikram Misri had visited Nepal during August 17-18 and met Mr. Oli and he was expected to visit India later this month. Mr. Misri had also met Foreign Minister Arzu Rana Deuba.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **नेपाल में अशांति:**

- भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और **सोशल मीडिया प्रतिबंध** से शुरू हुआ।
- "जेन-जेड विद्रोह" **के रूप में लेबल किए गए विरोध प्रदर्शनों के** कारण भारी झड़पें हुईं।
- पुलिस की गोलीबारी में **कम से कम** 19 युवकों की मौत।

2. **राजनीतिक नतीजा:**
   - प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तीन दिन की हिंसा के बाद इस्तीफा दे दिया है।
   - नेपाल सेना ने 9 सितंबर, रात 10 बजे से कानून-व्यवस्था की कमान संभाली।
3. **भारत की प्रतिक्रिया:**
   - **पीएम मोदी का बयान:** शांति के लिए नेपाली भाषा में अपील, नेपाल की "स्थिरता, शांति और समृद्धि" पर जोर दिया।
   - **विदेश मंत्रालय का बयान:** भारत घटनाक्रम की "बारीकी से निगरानी" कर रहा है, संवेदना व्यक्त कर रहा है और संयम और बातचीत का आग्रह कर रहा है।
   - **यात्रा परामर्श:** भारतीयों को यात्रा स्थगित करने के लिए कहा गया है; काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा हेल्पलाइन प्रदान की गई है।
4. **राजनयिक संदर्भ:**
   - विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नेपाल (17-18 अगस्त, 2025) का दौरा किया, पीएम ओली और विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की।
   - भारत तटस्थ रुख **बनाए रखता** है, किसी भी गुट का समर्थन करने की धारणा से बचता है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **भारत-नेपाल संबंध:**
  - यह 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि **से बंधा हुआ है**।
  - भारत → घनिष्ठ आर्थिक संबंध नेपाल का सबसे **बड़ा व्यापार भागीदार** और प्रमुख विकास भागीदार है।
  - प्रवासन, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के लिए खुली सीमा महत्वपूर्ण →।
- **भू-राजनीतिक संदर्भ:**
  - नेपाल रणनीतिक रूप से भारत और चीन के बीच स्थित है।
  - भारत पारंपरिक रूप से प्रभाव का दबदबा बना रहा है, लेकिन चीन बुनियादी**ढांचे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है**।
- **नेपाल में पिछली राजनीतिक अस्थिरता:**
  - राजशाही से गणतंत्र में संक्रमण (2008)।
  - बार-बार सरकार परिवर्तन, गठबंधन की अस्थिरता, संवैधानिक बहस।
  - 2015 में संविधान प्रख्यापन और मधेसी आंदोलन के दौरान इसी तरह के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. प्रीलिम्स पॉइंटर्स:

- शांति और मैत्री संधि, 1950 भारत-नेपाल संबंधों की आधारशिला →।
- खुली सीमा व्यवस्था भारत-नेपाल संबंधों की अनूठी विशेषता →।

2. मुख्य विश्लेषण (जीएस-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध):

- **भारत का संतुलन अधिनियम:**

- पिछले हस्तक्षेपों के विपरीत, भारत **तटस्थ, सतर्क दृष्टिकोण अपनाता है**→ किसी भी राजनीतिक खेमे को अलग-थलग करने से बचता है।
- उद्देश्य: बाहरी हस्तक्षेप की धारणा को रोकना, नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करना।

- **क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**
  - विरोध प्रदर्शन नेपाल में दीर्घकालिक शासन चुनौती के → गहरे पीढ़ीगत असंतोष को दर्शाता है।
  - भारत के साथ खुली सीमा पर **शरणार्थी/प्रवासन का दबाव** बढ़ सकता है।
  - नेपाल में अस्थिरता चीन के रणनीतिक प्रवेश को अधिक से अधिक अनुमति दे सकती है।
- **भारत के रणनीतिक हित:**
  - नेपाल में भारतीय नागरिकों (बड़ी संख्या में प्रवासी और तीर्थयात्री) की सुरक्षा।
  - बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: सीमा पार रेल, जल विद्युत, व्यापार गलियारे।
  - सुरक्षा: सीमा पार अपराध का मुकाबला करना, खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना।
- **राजनयिक उत्तोलन:**
  - भारत संवाद, संयम और शांति **पर जोर देता** है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है।
  - पीएम मोदी की नेपाली भाषा में अपील →सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक आत्मीयता।

निष्कर्ष

नेपाल में सामने आ रही हिंसा इसकी राजनीतिक प्रणाली की नाजुकता और जवाबदेह शासन की पीढ़ीगत मांग को उजागर करती है। भारत के लिए, चुनौती एक **करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में अपनी भूमिका** को संतुलित करने में है , जबकि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचना है जो कूटनीतिक रूप से उल्टा पड़ सकता है। एक शांतिपूर्ण और स्थिर नेपाल भारत की **सुरक्षा, व्यापार और पड़ोस नीति के लिए महत्वपूर्ण है**। तटस्थता, लोगों से लोगों के बीच संबंधों और रणनीतिक धैर्य से निर्देशित भारत का सतर्क दृष्टिकोण इसकी पड़ोसी पहले नीति की विकसित परिपक्वता को दर्शाता **है**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : भारत-नेपाल संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और नेपाल एक खुली सीमा साझा करते हैं जो लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देते हैं।

2. 1950 की शांति और मैत्री संधि भारत-नेपाल संबंधों का आधार है।

3. नेपाल सार्क और बिम्सटेक दोनों का सदस्य है।

4. नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(स) 1, 2, 3 और 4

(d) केवल 1 और 3

उत्तर : c)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: "नेपाल में सामने आ रही हिंसा इसकी राजनीतिक प्रणाली की नाजुकता और भारत की पड़ोस नीति की चुनौतियों को रेखांकित करती है। नेपाल संकट के प्रति भारत की सतर्क प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए।**(150 शब्द)**

Page 06 :GS 3 : Environment & Ecology/ Prelims

81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट **निकोबार द्वीप परियोजना** ने आदिवासी और वन अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से एक "तथ्यात्मक रिपोर्ट" मांगी है, क्योंकि **लिटिल एंड ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद** ने शिकायत की है कि लगभग 13,000 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन से पहले **वन अधिकार अधिनियम** (**एफआरए**), 2006 के तहत अधिकारों का निपटान नहीं किया गया था। यह मामला **रणनीतिक विकास परियोजनाओं और स्वदेशी अधिकारों की सुरक्षा के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालता है**।

Daily News Analysis

Union govt. seeks 'factual report' on forest rights complaint concerning Nicobar project

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

The Union government has sought a "factual report" from the Andaman and Nicobar Islands administration on points raised in a complaint by the Tribal Council of Little and Great Nicobar that forest rights had not been settled before diverting around 13,000 hectares for the ₹81,000-crore Great Nicobar Island project in August 2022.

In August, *The Hindu* reported about the complaint to Tribal Affairs Minister Jual Oram that the administration had made a "false" representation to the Centre in certifying that all rights under the Forest Rights Act (FRA) of 2006 had been identified and settled before diverting the required forest land for the project in the certificate issued on August 18, 2022.

The Andaman and Nicobar Island administration has maintained that it need not implement the Forest Rights Act of 2006. GETTY IMAGES

The council said its consent had been "obtained under pressure" and withdrawn formally soon after in a letter to the government. The certificate contradicted the administration's position in monthly FRA progress reports to the Ministry that it does not need to implement the Act.

In a letter to the Chief Secretary of the Union Territory on Monday, the Ministry asked for a "factual report addressing each of the points raised in the said news report and the letter of Tribal Council".

The Ministry said it had received the letter from the Tribal Council, "raising the issue that the Forest rights guaranteed to the Nicobarese in Great Nicobar Island have not been settled under the FRA, 2006, and Nicobarese have not consented to diversion of forest lands...".

Earlier this year, Mr. Oram said concerns over the project are being "examined". Weeks after sending the complaint to Mr. Oram in July, the Tribal Council said it had received no response.

The council then wrote to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on August 26, flagging the authorities' "refusal" to engage in dialogue with them. This prompted Mr. Gandhi to write to Mr. Oram last week, urging his office to examine the concerns raised by the council.

On Monday, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, in an article in *The Hindu*, criticised the Centre over this project, calling it a "planned misadventure". After sending the complaint to Mr. Oram, a member of the Tribal Council told *The Hindu* that it had recently been made aware of the August 2022, certificate issued by the Deputy Commissioner of Nicobar, certifying, "The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out..." But the Tribal Council said that the process of identification and settlement of rights under the FRA "has not even been initiated".

According to the progress reports, the administration has maintained that it does not need to implement the FRA, arguing that tribespeople's rights were already protected on the islands under the Protection of Aboriginal Tribes Act, 1956 which enables the administration to unilaterally divert forest land.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. **जनजातीय परिषद द्वारा शिकायत (2022-2025):**
   - आरोप लगाया कि वन भूमि के डायवर्जन के लिए सहमति 'दबाव में' ली गई और बाद में वापस ले ली गई।
   - प्रशासन ने केंद्र को झूठा प्रमाणित किया (18 अगस्त, 2022) कि एफआरए अधिकारों का निपटान कर दिया गया था।
   - मंत्रालय को सौंपी गई प्रगति रिपोर्ट में दावा किया गया है कि **निकोबार में** एफआरए को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:**
   - जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से "तथ्यात्मक रिपोर्ट" मांगी है।
   - एफआरए कार्यान्वयन पर सवाल उठाया गया, क्योंकि निकोबारी आदिवासी अधिकारों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया।
3. **राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ:**
   - जनजातीय परिषद ने जनजातीय मामलों के मंत्री जुआलओरम (जुलाई 2025) से संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
   - बाद में राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन्होंने मंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
   - सोनिया गांधी ने इस परियोजना को "नियोजित दुस्साहस" कहा।
4. **परियोजना पृष्ठभूमि:**
   - परियोजना का उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और टाउनशिप** है।
   - ~13,000 हेक्टेयर प्राचीन जंगल के डायवर्जन की आवश्यकता है, जो **शोम्पेन और निकोबार जनजातियों को प्रभावित करता है**।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **वन अधिकार अधिनियम (2006):**
  - वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी (अन्य पारंपरिक वन निवासियों) के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
  - वन अपवर्तन से पहले **ग्राम सभा की सहमति** की आवश्यकता होती है।
- **आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन (PATR), 1956:**
  - अंडमान और निकोबार में जनजातीय कल्याण को नियंत्रित करता है।
  - प्रशासन का तर्क है कि पीएटीआर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए एफआरए को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
- **संवैधानिक समर्थन:**
  - अनुच्छेद 244 और पांचवीं/छठी अनुसूची: अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान।
  - अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की निगरानी।
- **सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल:**
  - *उड़ीसा खनन निगम बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय* (2013, *नियमगिरी मामला*)→ एफआरए के तहत वन भूमि के अपवर्तन के लिए जनजातीय सहमति अनिवार्य है।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. प्रीलिम्स पॉइंटर्स:

- एफआरए 2006 ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य →।
- पीएटीआर 1956 औपनिवेशिक युग का कानून →, जो अंडमान और निकोबार के लिए विशिष्ट है।
- ग्रेट निकोबार परियोजना →₹81,000 करोड़, ~13,000 हेक्टेयर वन डायवर्जन।

2. मुख्य विश्लेषण (जीएस-II, जीएस-III, जीएस-वी):

- **कानूनी-प्रशासनिक संघर्ष:**
  - एफआरए (2006) एक केंद्रीय कानून है → पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन यूटी प्रशासन पीएटीआर 1956 के तहत छूट का दावा करता है।
  - आदिवासी अधिकारों के प्रवर्तन में संघीय स्थिरता **पर सवाल उठाता है**।
- **विकास बनाम स्वदेशी अधिकार:**
  - परियोजना को रणनीतिक (भारत की एक्ट ईस्ट नीति, शिपिंग हब) के रूप में उचित ठहराया गया।
  - लेकिन पारिस्थितिक संतुलन (वर्षावन, जैव विविधता) और **शोम्पेन जैसे** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है।
- **दबाव में सहमति:**
  - "जबरन सहमति" के आरोप **स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी)** की भावना को कमजोर करते हैं।
  - जनजातीय सहमति वापस लेना **प्रक्रियात्मक अनियमितता को** इंगित करता है।
- **शासन और पारदर्शिता के मुद्दे:**
  - जारी किए गए प्रमाण पत्र (2022) ने दावा किया कि अधिकार →निपटा गए लेकिन प्रगति रिपोर्ट में कहा गया कि एफआरए लागू नहीं है।
  - प्रशासनिक जवाबदेही और डेटा रिपोर्टिंग **में विरोधाभासों को दर्शाता है**।
- **राजनीतिक संवेदनशीलता:**
  - विपक्ष सरकार पर दबाव बढ़ाने → मुद्दा उठा रहा है।

- आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण शासन पर राष्ट्रीय स्तर की बहस **बन सकती है**।

- **भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए निहितार्थ:**
  - भारत की UNDRIP (स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा) **के तहत प्रतिबद्धताएं हैं**।
  - स्वदेशी अधिकारों को कमजोर करने वाली परियोजनाएं वैश्विक जांच को आकर्षित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

निकोबार परियोजना भारत के शासन में क्लासिक **विकास बनाम अधिकारों की दुविधा** का प्रतीक है । जबकि भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, यह **वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, आदिवासी सहमति और पारिस्थितिक स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है**। तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगने का सरकार का निर्णय एक कदम आगे है, लेकिन इसे हल करने के लिए आवश्यक है:

- एफआरए के तहत जनजातीय अधिकारों का पारदर्शी निपटान।
- निर्णय लेने में वास्तविक सामुदायिक भागीदारी।
- संवैधानिक और पारिस्थितिक जिम्मेदारियों के साथ रणनीतिक बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों **को संतुलित करना**।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।

2. यह अधिनियम केवल मुख्य भूमि भारत पर लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर नहीं।

3. अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों वन अधिकारों को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर :c)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रणनीतिक विकास और पारिस्थितिक-जनजातीय अधिकारों के बीच क्लासिक दुविधा को दर्शाता है। चुनौतियों का विश्लेषण करें और उन्हें हल करने के उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

Page 11 :GS 1 : Social Issues / Prelims

भारत में शहरीकरण अक्सर **अनियोजित विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कमजोर स्थानीय शासन** की विशेषता है। तेजी से "रूर्बन" परिवर्तन और जलवायु तनाव का सामना कर रहे केरल ने **दिसंबर 2023 में केरल शहरी नीति आयोग (KUPC) की स्थापना की** , जो भारत का पहला राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है। इसकी **2025 की रिपोर्ट** जलवायु लचीलापन, वित्त, शासन और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करने वाला **25 साल का रोडमैप** प्रदान करती है, जो शेष भारत के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है।

EXPLAINER

Rejuvenating cities: A fisherman casting his net into the backwaters, in Kochi. H.VIBHU

Lessons for India: how Kerala is tackling rapid urbanisation

As the first State-level urban commission in the country, the Kerala Urban Policy Commission's report promises nothing less than a data revolution, governance recalibration, identity revival, and finance empowerment

Tikender Singh Panwar

The story so far:

Kerala is a tapestry of villages rippling into towns, of backwaters, and midlands and highlands woven together in a living continuum. Capital cities and hamlets bleed into each other, forming a unique "rurban" landscape. Yet beneath this tapestry lies a race against time – urbanisation accelerating faster than infrastructure and governance can keep up, while climate stress lurks in floods, landslides, coastal erosion, and unpredictable weather. In response, Kerala decided to tackle the problem head-on with the Kerala Urban Policy Commission.

What is the KUPC?

The Kerala Urban Policy Commission, (KUPC) set in motion in December 2023, was charged with designing a 25-year urban roadmap that sees cities not as concrete problems, but as organic, climate-aware ecosystems. When the KUPC handed its report to the State in March 2025, the result was not a mild adjustment – it was a structural reset. The blueprint promised nothing less than a data revolution, governance recalibration, identity revival, and finance empowerment – all tied together in one bold vision.

Why was it needed?

By late 2023, Kerala was urbanising at a pace well ahead of the national average. Estimates projected an urban population of over 80% by 2050 – a seismic shift in a region where villages and towns intermesh in a delicate mosaic. Meanwhile, climate threats were intensifying. Floods devastated Ernakulam; landslides shattered hillsides; and coastal zones reeled from sea-level pressures. The gap between crisis and planning was growing wide.

The cabinet's December 2023 resolution to form the KUPC was a calculated break from India's centralised, project-based urban model. It was a political acknowledgement that Kerala needed its own compass – tailored to its place, history, and climate context. No other State had taken such a leap. Therefore, the KUPC became India's first State-level urban commission, signalling a paradigm shift – from reactive fixes to systemic thinking.

What were the recommendations of the commission?

The commission conducted 33 deep-dive studies, covering everything from land-use patterns and water systems to finance flows and civic health. It held 53 district-level stakeholder dialogues, involving mayors, NGOs, unions, resident associations, gig workers, and panchayat members.

A 2,359-page final report, structured around 10 thematic pillars, ranging from climate readiness and finance to well-being and identity, was submitted to the State. The commission drew on Census numbers, satellite imagery, socio-economic realities, ecological hazards, and Kerala's lived "rurban" character to deliver actionable insights grounded in evidence and local narrative.

Some of the most important recommendations of the KUPC report submitted to the Chief Minister on March 30, 2025 include:

Climate and risk-aware zoning: Any kind of urban planning must reflect hazard mapping of landslides, coastal inundation, flood zones etc. Thus, planning becomes proactive, instead of being reactive.

A digital data observatory: At the Kerala Institute of Local Administration, a real-time data nerve centre could collate high-resolution Light Detection and Ranging, and ground penetrating radar, tide/water gauge, satellite and real-time weather data. Thus, every municipality gains a living intelligence feed.

Green fees and climate insurance: Projects in eco-sensitive zones could come with environmental levies (green fees) which would fund urban resilience. A parametric insurance model ensures pre-approved payouts for disaster-prone areas.

Municipal and pooled bonds: While Thiruvananthapuram, Kochi, and Kozhikode, being bigger cities, could issue municipal bonds, smaller towns would use pooled instruments. Bond subscriptions were even plugged into the 2024 interim Budget.

Governance overhaul: City cabinets, led by mayors, could replace bureaucratic inertia. Specialist cells (climate, waste, mobility, law) with dedicated municipal cadres should be formed. A "Jnanashree" program would recruit and deploy youth tech talent.

Place-based economic revival: Thrissur-Kochi is known as a FinTech hub; Thiruvananthapuram-Kollam a knowledge corridor; Kozhikode is known as the city of literature; and Palakkad and Kasaragod have been elevated to smart industrial zones.

Commons, culture, and care: The report stressed the need to revive wetlands, reactivate waterways and preserve heritage zones. It also recommended city health councils to cater to migrants, students, gig workers.

Why is the report unique?

The KUPC highlighted a deeper innovation: the fusion of local narratives and data systems.

Commission members described how fishermens' ordeals with coastal recession, youth-crafted water conservation drives, or mobility woes voiced by bazaar vendors – all became structured into the urban data apparatus. LIDAR maps now register tidal health near fishing zones; municipal dashboards carry community-generated indicators; and city briefing templates reflect lived stories. Rather than imposing "top-down solutions," policies were co-produced with citizens, giving Kerala an urban intelligence engine – a living, breathing system where city systems absorb, interpret and act on the emotional, lived intelligence of local communities.

What distinguishes the KUPC isn't one big idea – it's the collision of several game-changing ones.

The KUPC is the first State-level commission built for sub-national realities and not recycled from national frameworks. In its report, climate resilience is embedded and not appended – every pillar integrates disaster awareness. The report also calls for the emancipation of public finance through municipal bonds and green levies which give local bodies fiscal agency.

It also re-defines governance from passive bureaucracies to dynamic election-led city cabinets, guided by youth technocrats. Rich stories fuel data, and data fuels policy, closing the feedback loop between lived reality and institutional action. Together, these features dismantle silos – in planning, finance, governance – and re-assemble them into a 360° urban system.

Does it offer lessons for other States?

Kerala's Urban Commission offers a template with tangible takeaways for other States – mandate a time-bound commission; combine technical data with lived experience and create dialogic systems where citizen inputs are mapped into data observatories; empower local bodies with green levies, bonds, and risk premiums; and insert youth and specialists in governance.

What next?

The KUPC changed more than planning – it rewired the DNA of how a State conceives its cities and towns. It entwined climate awareness, community narrative, financial empowerment, digital governance, and identity economy into a living document-functional plan.

As the first such State-level commission in the country, KUPC isn't an end – it's a beginning. For Kerala, it's a chance to grow not just richer, but wiser; not just bigger, but better; not just more urban, but more human.

For others, it's a call to action: urban transformation isn't a problem to solve. It's a story to be authored – together.

Tikender Singh Panwar is a Member of the KUPC and a former deputy mayor, Shimla.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

- केरल की **शहरी आबादी 2050 तक 80% को पार करने का अनुमान है।**
- बढ़ते खतरे: बाढ़, भूस्खलन, तटीय कटाव, जलवायु परिवर्तनशीलता।
- **KUPC (2023-25):** शहरों को जैविक, जलवायु-जागरूक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में फिर से कल्पना करने के लिए अनिवार्य किया गया।
- 2,359 पन्नों की रिपोर्ट (मार्च 2025) **प्रस्तुत की, जिसमें** 10 विषयगत स्तंभों को संरचित किया गया है – **लचीले और समावेशी शहरीकरण के लिए एक खाका।**

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **भारत में शहरीकरण:** 35% शहरी जनसंख्या (जनगणना 2011), 2050 तक 50%+ तक पहुंचने का अनुमान है।
- **चुनौतियां:** बुनियादी ढांचे की कमी, झुग्गी-झोपड़ियां, पानी की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, कमजोर शहरी वित्त।
- **योजनाएं:** स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, पीएमएवाई-शहरी → ज्यादातर **परियोजना-आधारित, केंद्रीकृत मॉडल।**

- **संवैधानिक ढांचा:** 74वां संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सशक्त →, लेकिन राजकोषीय और कार्यात्मक स्वायत्तता कमजोर बनी हुई है।
- **जलवायु संदर्भ:** 2018 की बाढ़, बार-बार भूस्खलन, तटीय जलप्लावन →केरल की भेद्यता।

KUPC की प्रमुख सिफारिशें

1. **जलवायु और जोखिम-जागरूक ज़ोनिंग**
   - बाढ़, भूस्खलन, तटीय कटाव के लिए खतरे का मानचित्रण योजना में एकीकृत किया गया है।
2. **डिजिटल डेटा वेधशाला**
   - केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रीयल-टाइम डेटा हब (LIDAR, उपग्रह, मौसम फ़ीड)।
   - सभी नगर पालिकाओं के लिए साक्ष्य-आधारित योजना।
3. **शहरी वित्त सशक्तिकरण**
   - नगरपालिका और पूल किए गए बांड।
   - पर्यावरण के प्रति संवेदनशील परियोजनाओं के लिए हरित शुल्क और जलवायु बीमा।
4. **शासन सुधार**
   - **नौकरशाही प्रभुत्व की जगह महापौरों के नेतृत्व में** शहर की मंत्रिमंडलियां।
   - विशेषज्ञ कोशिकाएं (जलवायु, अपशिष्ट, गतिशीलता)।
   - **नगर पालिकाओं में युवा तकनीकी प्रतिभाओं को तैनात करने के लिए** "ज्ञानश्री" कार्यक्रम।
5. **आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरोद्धार**
   - क्षेत्र-आधारित क्लस्टर: फिनटेक हब (त्रिशूर-कोच्चि), नॉलेज कॉरिडोर (तिरुवनंतपुरम-कोल्लम)।
   - आर्द्रभूमि, जलमार्ग, विरासत का संरक्षण।
   - प्रवासियों, गिग श्रमिकों के लिए नगर स्वास्थ्य परिषद।
6. **समुदाय-संचालित डेटा सिस्टम**
   - योजना (मछुआरे, विक्रेता, युवा समूह) में एकीकृत नागरिक कथाएं।
   - **बॉटम-अप इंटेलिजेंस फीडिंग** पॉलिसी डिजाइन।

प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विश्लेषण

1. प्रीलिम्स पॉइंटर्स:

- केरल शहरी नीति आयोग 2023 →, पहला राज्य-स्तरीय शहरी आयोग।
- जलवायु, वित्त, शासन, संस्कृति, पहचान आदि → 10 स्तंभ।
- नगरपालिका बांड, पूल किए गए बांड, ग्रीन लेवी की सिफारिश की जाती है।

2. मुख्य प्रासंगिकता (जीएस-I/II/III):

- **शासन नवाचार:** केंद्रीकृत स्मार्ट सिटी दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है; यूएलबी को वित्त और अधिकार के साथ सशक्त बनाता है।
- **जलवायु मुख्यधारा:** अधिकांश भारतीय शहरी योजनाओं के विपरीत, जहां लचीलापन एक "ऐड-ऑन" है, यहाँ यह अंतर्निहित है।
- **डेटा क्रांति:** वास्तविक समय वेधशालाएं वैज्ञानिक डेटा →साक्ष्य-आधारित + भागीदारी योजना) के साथ स्थानीय आख्यानों को एकीकृत करती हैं।

- **राजकोषीय संघवाद:** नगरपालिका बांड और स्थानीय संसाधन जुटाने को बढ़ावा देता है, राज्य/केंद्र अनुदान पर निर्भरता को कम करता है।
- **नागरिक-केंद्रित मॉडल:** शहरी डिजाइन (समावेशी योजना के संयुक्त राष्ट्र-आवास सिद्धांत) में जीवित अनुभवों को शामिल करता है।
- **अन्य राज्यों के लिए टेम्पलेट:** समयबद्ध कमीशन **की संभावना को दर्शाता** है जो पारिस्थितिकी के साथ विकास को संतुलित करता है।

निष्कर्ष

केरल के केयूपीसी ने परियोजना-आधारित सुधारों से प्रणालीगत सोच में बदलाव **करके भारत में शहरी नियोजन को फिर से परिभाषित किया है**। यह एक प्रतिकृति टेम्पलेट प्रदान करता है:

- वित्त और शासन स्वायत्तता **के साथ स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना**।
- योजना के हर चरण में **जलवायु और आपदा लचीलापन को** एकीकृत करें।
- संदर्भ-संवेदनशील नीतियों के लिए **डिजिटल डेटा के साथ नागरिक कथाओं को** फ्यूज करें।

भारत के लिए, जहां शहरीकरण अपरिहार्य है, सबक स्पष्ट है: **शहरों को जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए - न कि केवल विकास इंजन।** केरल का दृष्टिकोण दिखाता है कि शहरीकरण को न केवल स्मार्ट बनाया जाए**, बल्कि अधिक टिकाऊ, समावेशी और मानवीय भी बनाया जाए।**

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा/से केरल शहरी नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशों का हिस्सा है/हैं?

1. शहरी नियोजन में खतरे का मानचित्रण और जलवायु-जोखिम ज़ोनिंग।

2. पर्यावरण-संवेदनशील परियोजनाओं के लिए हरित शुल्क और जलवायु बीमा।

3. नौकरशाही के नेतृत्व वाले शहर प्रशासन को निर्वाचित शहर मंत्रिमंडलों के साथ प्रतिस्थापित करना।

4. शहरी वित्त के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर विशेष निर्भरता।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: बी)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: केरल शहरी नीति आयोग (2023-25) शहरी शासन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। 74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के संदर्भ में इसकी सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

Daily News Analysis

The long march ahead to technological independence

India celebrated its hard-won political freedom on the 79th Independence Day, on August 15, 2025. But we must recognise that true independence today requires more than political autonomy. It also demands technological sovereignty, as technology aids every walk of life today.

Geopolitics has taken a darker turn recently. Modern wars are fought with software and drones, not bullets and bombs. The most damaging war is in cyberspace. Our banks, trains and power grids run on information and communication technology. A small number of companies, primarily from a single country, build and control these systems.

This dependence is a serious vulnerability. What happens if these companies turn off their cloud or Artificial Intelligence services under national diktat or out of malice? The capacity to inflict serious harm on the country is very real. We saw this when cloud services were stopped to a company recently. This is not a hypothetical threat, but a reality that we must confront.

Building the foundation

Technological autonomy is the solution. India has no operating system, database, or other foundational software that it builds and can trust completely. This leaves the country dependent on external sources that its cannot control or trust. However, the path to independence is not as difficult as it might seem.

The open-source model offers a path to a solution. India can create its own versions of Linux and Android that are safe and free of backdoors. It is possible for a dedicated group of professionals to do this. The real challenge lies in long-term support and maintenance. A large, supportive user base is necessary for a home-grown operating system (OS) to be viable. If we are to adopt an OS that is a little behind, we can make them competitive and viable. This is a mission for India's sizeable technology community. The problem affects everyone, but the solution lies with IT professionals who build the digital world. They must join hands to remove this debilitating dependence. This is too big a task for any single institution, but is achievable if many unite behind this goal.

P.J. Narayanan

is Professor and former Director of IIIT Hyderabad, and a researcher in computer vision, computer graphics and parallel computing

True independence today demands that India pursues technological sovereignty, as dependence is now a vulnerability

The path to hardware sovereignty

Achieving hardware sovereignty is a greater challenge than software sovereignty. Building sophisticated semi-conductor fabs requires massive, long-term national investment in chip design, manufacturing and supply chain management. Do we have the resources and, more importantly, the patience to build them? A crucial first step is to focus on specific hardware components and invest in partnerships to build expertise in chip design and assembly, even if fabrication is outsourced.

India's journey to political independence was defined by non-violence. Its quest for technology independence should be through open-source software, which is a gift of society to itself. This is about supporting ourselves and not opposing others.

The global open-source movement is no longer the powerful socio-political force that it was. Much of the software today is open-source, including Android, Linux, and Hadoop. However, key control is with centralised cloud and data managed externally by powerful companies. A social movement for autonomy in software and hardware is needed today. India has the necessary talent and the capability. The way exists.

What India needs is the collective will. Let it start an urgent mission of planning, development, and execution before a crisis forces its hand.

Assembling a crack team to create India's own versions of essential software from the open source resources is the first step. India must build client-side components (such as database, email client, calendar) and server-side components such as web server, email server, and cloud server. Open source versions are available for all of them. India needs to set up teams to continually update and maintain these components, which is the harder task. These teams should work like product teams in companies. This is possible only when there is a sound business model behind it, outside of government or private funds. The mission has to be self-supporting or better.

While this may have been a difficult idea to sell in the past, the current climate is different. Previously, only the strategic sectors were concerned with having trusted and secure software. Now, private companies and individuals are concerned about being dependent on outside forces for critical needs. People are already paying, either directly or indirectly, for the free and open-source software that they use. The shift to a model where these costs are explicit and support trusted software would be a small one.

A mission as the core

The immediate step is to establish a mission to plan the necessary actions. This will be an implementation mission and not a research and development mission aimed at academic/research communities. It will primarily involve strong development and support teams of engineers and a capable project management team to coordinate activities.

There is ample expertise in both industry and academia to make it happen, provided a viable model is established. The government will need to play an enabling role, but should focus on establishing a self-sustaining model as early as possible.

Let us embark on the long march toward technological independence.

GS. Paper 03 –विज्ञान प्रौद्योगिकी

UPSC Mains Practice Question:भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता तकनीकी स्वतंत्रता के बिना अधूरी रहेगी।" भारत के लिए तकनीकी संप्रभुता की आवश्यकता पर चर्चा करें और इसे प्राप्त करने के उपाय सुझाएँ।(150 Words)

संदर्भ:

भारत ने **2025 में अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस** मनाया, लेकिन अकेले राजनीतिक संप्रभुता **सच्ची स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती है**। आज की दुनिया में, **तकनीकी संप्रभुता** महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं, सुरक्षा और शासन कुछ वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा नियंत्रित डिजिटल सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

- आधुनिक युद्ध तेजी से साइबर-संचालित होते जा रहे हैं - ड्रोन, एआई, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (बैंकों, ग्रिड, रेलवे) पर साइबर हमले।
- विदेशी क्लाउड, एआई और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर निर्भरता भारत को **गंभीर कमजोरियों के लिए उजागर करती है**।
- उदाहरण: क्लाउड सेवाओं को किसी कंपनी से काट दिया जा रहा है, जिससे वास्तविक दुनिया के जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है।
- **भारत में स्वदेशी मूलभूत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकोसिस्टम का अभाव है**।
- ओपन-सोर्स मॉडल का लाभ उठाते हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वायत्तता बनाने के लिए **एक राष्ट्रीय मिशन** का आह्वान करें।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **तकनीकी संप्रभुता:** बाहरी निर्भरता के बिना महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे को डिजाइन, निर्माण और नियंत्रित करने की राष्ट्र की क्षमता।
- **भारत की वर्तमान स्थिति:**
  - आयातित हार्डवेयर (अर्धचालक, सर्वर) पर भारी निर्भरता।
  - सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम (ओएस, क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटाबेस) पर यू.एस.-आधारित निगमों का प्रभुत्व है।
  - बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरे →उदाहरण के लिए, एम्स पर रैंसमवेयर हमले (2022), बार-बार पावर ग्रिड साइबर हमले।
- **प्रासंगिक नीतियां और पहल:**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019
  - ₹76,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021)।
  - डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया।

पहचाने गए प्रमुख मुद्दे

1. **सॉफ्टवेयर निर्भरता:**
   - भारत में अपने स्वयं के ओएस, डेटाबेस या क्लाउड प्लेटफॉर्म का अभाव है।
   - मालिकाना अमेरिकी प्लेटफार्मों (माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडब्ल्यूएस) पर निर्भरता।
2. **हार्डवेयर भेद्यता:**
   - कोई स्वदेशी अर्धचालक फैब नहीं।
   - आपूर्ति श्रृंखलाएं पूर्वी एशिया में केंद्रित हैं।
   - भू-राजनीतिक तनाव के दौरान व्यवधान का जोखिम।

3. **ओपन-सोर्स क्षमता:**
    - लिनक्स, एंड्रॉइड, हडूप उपलब्ध→ लेकिन दीर्घकालिक समर्थन, अनुकूलन और उपयोगकर्ता आधार **की आवश्यकता है**।
    - चुनौती: स्थायी वित्त पोषण और रखरखाव।
4. **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
    - विदेशी तकनीक में बैकडोर का फायदा उठाया जा सकता है।
    - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा (बैंकिंग, रक्षा, पावर ग्रिड) रिमोट शटडाउन के प्रति संवेदनशील हैं।

आगे की राह/सिफारिशें

1. **सॉफ्टवेयर संप्रभुता:**
    - स्वदेशी ओएस (लिनक्स/एंड्रॉइड-आधारित, सुरक्षा जांच के साथ) बनाएं।
    - क्लाइंट-साइड (डेटाबेस, ईमेल, कैलेंडर) और सर्वर-साइड (वेब, क्लाउड, मेल) समाधान विकसित करें।
    - निजी कंपनियों की तरह "उत्पाद टीमों" → निरंतर अद्यतन टीमों की स्थापना करें।
2. **हार्डवेयर संप्रभुता:**
    - सबसे पहले चिप डिज़ाइन और असेंबली साझेदारी **पर ध्यान दें**।
    - वैश्विक सहयोग के साथ फैब में दीर्घकालिक निवेश।
    - फैबलेस स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
3. **सामाजिक आंदोलन के रूप में ओपन-सोर्स:**
    - भारत के बड़े आईटी कार्यबल को सहयोगी राष्ट्रीय परियोजनाओं में जुटाना।
    - शुद्ध सरकारी निर्भरता के बजाय टिकाऊ व्यापार मॉडल (सदस्यता, सहायता सेवाएं) बनाएं।
4. **संस्थागत मिशन:**
    - तकनीकी स्वतंत्रता पर एक राष्ट्रीय मिशन **शुरू करना**।
    - कार्यान्वयन-संचालित, अकादमिक नहीं।
    - शिक्षा + उद्योग विशेषज्ञ + स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र शामिल करें।
    - सरकार एकमात्र फंडर की नहीं, बल्कि **सुविधा प्रदाता की भूमिका** निभाएगी।

यूपीएससी के लिए विश्लेषण

प्रीलिम्स पॉइंटर्स

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021)।
- वन अधिकार अधिनियम (2006) बनाम आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अधिनियम (1956) (पहले निकोबार क्यू से)।
- लिनक्स और एंड्रॉइड ओपन-सोर्स मूलभूत सॉफ्टवेयर के उदाहरण →।

मेन्स (जीएस-III: एस एंड टी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था)

- **गंभीरता:** तकनीकी निर्भरता = रणनीतिक भेद्यता।
- **अवसर:** भारत का बड़ा आईटी प्रतिभा पूल + स्टार्टअप संस्कृति।
- **चुनौतियां:** धन की कमी, खंडित पारिस्थितिकी तंत्र, स्वदेशी फैब की अनुपस्थिति।
- **तुलनात्मक अंतर्दृष्टि:**
    - अमेरिका और चीन एआई, क्वांटम, चिप्स में भारी निवेश कर रहे हैं।

- यूरोपीय संघ GDPR, Gaia-X (क्लाउड इंडिपेंडेंस) के माध्यम से "तकनीकी संप्रभुता" को आगे बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष

1947 में भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी। लेकिन 2025 में, **सच्ची स्वतंत्रता के लिए तकनीकी संप्रभुता की आवश्यकता होती है**। स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण वैकल्पिक नहीं है - यह **आर्थिक लचीलापन, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए आवश्यक है**। आगे का रास्ता एक**सामूहिक राष्ट्रीय मिशन** है जो ओपन-सोर्स इनोवेशन, टिकाऊ बिजनेस मॉडल और हार्डवेयर में दीर्घकालिक निवेश का संयोजन करता है।

तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा अपने स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही एक **शांतिपूर्ण, सहयोगी और समावेशी मार्च** होनी चाहिए - यह सुनिश्चित करना कि देश की डिजिटल रीढ़ **भरोसेमंद, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार** हो।

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

Daily News Analysis

Follow More:-

- **Phone Number :- 9999154587**
- **Email :-** k.nitinca@gmail.com
- **You Tube : - https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram : - https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook:https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**